

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	श्रावण 30, शुक्रवार, शाके 1942-अगस्त 21, 2020 <i>Sravana 30, Friday, Saka 1942-August 21, 2020</i>	

**भाग-3(क)**

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत  
करने से पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 21, 2020

संख्या एफ. 13(23)विशा/विस/2020 :-राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2020 जैसा कि दिनांक 21 अगस्त, 2020 को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया,सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रमिल कुमार माथुर,  
सचिव।

**Bill No.23 of 2020**

**THE RAJASTHAN EXCISE (AMENDMENT) BILL, 2020**

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

*Bill*

*further to amend the Rajasthan Excise Act, 1950.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Excise (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 1<sup>st</sup> June, 2020.

**2. Amendment of heading of Chapter V, Rajasthan Act No. II of 1950.-** For the existing heading of Chapter V “Duties and Fees” of the Rajasthan Excise Act, 1950 (Act No. II of 1950), hereinafter referred to as the principal Act, the heading “Duties, Fees and Surcharge” shall be substituted.

**3. Insertion of section 28-A, Rajasthan Act No. II of 1950.-** After the existing section 28 and before the existing section 29 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

**“28-A. Surcharge for mitigating natural or man-made calamities.-** (1) Any excisable article chargeable with duty under section 28, shall be chargeable with surcharge at such rate not exceeding 50 percent of the duty chargeable on such

excisable article under section 28, as may be notified by the State Government, for the purpose of mitigating natural or man-made calamities like drought, flood, epidemic, public health exigencies, fire etc.

(2) The surcharge chargeable under sub-section (1) shall be in addition to any duty under section 28.

(3) Except as otherwise provided in sub-section (1), provisions of this Act shall, so far as may be, apply in relation to the surcharge, leviable under sub-section (1) as they apply in relation to the duty leviable under section 28.

(4) Save as provided in sub-section (3), the State Government may make rules for collection of surcharge leviable under this section.

(5) The surcharge collected under this section shall be utilized for the purpose of mitigating natural or man-made calamities like drought, flood, epidemic, public health exigencies, fire etc.”.

**4. Repeal and savings.-** (1) The Rajasthan Excise (Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 6 of 2020) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

---

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

With the enactment of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 the State has limited powers for taxation and additional funds are required for the purposes of mitigating natural or man-made calamities like drought, flood, epidemic, public health exigencies, fire etc. The State is currently in grip of the COVID-19 pandemic and financial resources have been reduced both due to falling revenues as a result of economic standstill and the rising contingency expenses which are needed to combat this public health emergency. Therefore, in order to generate the funds, the State Government has decided to make amendment in the Rajasthan Excise Act, 1950. Accordingly, a new section 28-A in the Rajasthan Excise Act, 1950 is proposed to be inserted so as to levy a surcharge at such rate not exceeding 50 percent of the duty on excisable items as may be notified by the State Government.

Since, the Rajasthan State Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the Rajasthan Excise (Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 6 of 2020) on 1<sup>st</sup> June, 2020, which was published in Rajasthan Gazette, Extraordinary, Part IV(B), dated 2<sup>nd</sup> June, 2020.

The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत,  
**Minister Incharge.**

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

Clause 3 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules for collection of surcharge leviable under section 28-A.

The proposed delegation is of normal character and mainly relates to the matters of detail.

अशोक गहलोत,  
**Minister Incharge.**

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

---

A

*Bill*

*further to amend the Rajasthan Excise Act, 1950.*

---

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

---

Pramil Kumar Mathur,  
**Secretary.**

**2020 का विधेयक सं.23****(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)****राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2020****(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)**

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह 1 जून, 2020 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

**2. 1950 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 के अध्याय - V के शीर्षक का संशोधन.-** राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (1950 का अधिनियम सं. 2), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, के अध्याय- V के विद्यमान शीर्षक "शुल्क और फीस" के स्थान पर शीर्षक "शुल्क, फीस और अधिभार" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

**3. 1950 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 में धारा 28-क का अंतःस्थापन.-** मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 28 के पश्चात् और विद्यमान धारा 29 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

**"28-क. प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं के शमन के लिए अधिभार.-** (1) धारा 28 के अधीन शुल्क से प्रभार्य कोई आबकारी योग्य वस्तु ऐसी दर पर अधिभार से प्रभार्य होगी, जो धारा 28 के अधीन ऐसी आबकारी योग्य वस्तु पर प्रभार्य शुल्क के पचास प्रतिशत से अधिक न हो, जो राज्य सरकार द्वारा सूखा, बाढ़, महामारी, लोक स्वास्थ्य अत्यावश्यकताओं, अग्नि इत्यादि जैसी प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं के शमन के प्रयोजन के लिए, अधिसूचित की जाये।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रभार्य अधिभार धारा 28 के अधीन किसी शुल्क के अतिरिक्त होगा।

(3) उप-धारा (1) में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उप-धारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय अधिभार के संबंध में इस अधिनियम के उपबंध, जहां तक हो सके, वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे धारा 28 के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क के संबंध में लागू होते हैं।

(4) उप-धारा (3) में यथा उपबंधित के सिवाय, राज्य सरकार इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय अधिभार के संग्रहण के लिए नियम बना सकेगी।

(5) इस धारा के अधीन संगृहीत अधिभार का उपयोग सूखा, बाढ़, महामारी, लोक स्वास्थ्य अत्यावश्यकताओं, अग्नि इत्यादि जैसी प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं के शमन के प्रयोजन के लिए किया जायेगा।"

**4. निरसन और व्यावृत्तियां.-** (1) राजस्थान आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश सं. 6) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

**उद्देश्यों और कारणों का कथन**

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की अधिनियमिति से, राज्य के पास कराधान की सीमित शक्तियां रह गयी हैं और सूखा, बाढ़, महामारी, लोक स्वास्थ्य अत्यावश्यकताओं, अग्नि इत्यादि जैसी प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं के शमन के प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। वर्तमान में राज्य कोविड-19 महामारी की गिरफ्त में है और आर्थिक गतिरोध के परिणामस्वरूप राजस्व में गिरावट आने और आकस्मिक खर्चों में वृद्धि होने, दोनों के कारण वित्तीय संसाधनों में कमी आयी है, जो इस लोक स्वास्थ्य आपात का मुकाबला करने के लिए आवश्यक हैं। इसलिए, राज्य सरकार ने निधि सृजित करने के उद्देश्य से राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 में संशोधन करने का विनिश्चय किया है। तदनुसार, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 में नयी धारा 28-क को अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है ताकि आबकारी योग्य वस्तुओं पर प्रभार्य शुल्क के पचास प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये, अधिभार का उद्ग्रहण किया जा सके।

चूंकि राजस्थान राज्य विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 1 जून, 2020 को राजस्थान आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश सं. 6) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4(ख) में दिनांक 2 जून, 2020 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,  
प्रभारी मंत्री।

**प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन**

विधेयक का खण्ड 3, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को धारा 28-क के अधीन उद्ग्रहणीय अधिभार के संग्रहण के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और मुख्यतः ब्यौरे के विषय से संबंधित है।

अशोक गहलोत,  
प्रभारी मंत्री।



राजस्थान विधान सभा

---

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

---

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

---

प्रमिल कुमार माथुर,  
सचिव।

---

Government Central Press, Jaipur.